न दुनियावी न चुनावी

बाजीगरी अब तो वित्तमंत्री पी चिदंबरम बहुत खुश होंगे। आखिर उन्होंने संप्रग-दो सरकार का आखिरी बजट पेश कर दिया है। वह भी इतनी कारीगरी से कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यानी अपना मकसद भी पूरा हो जाए और किसी का बुरा भी न हो। महिला, युवा और गरीब को केंद्र में रखकर पेश इस बजट में अन्य सभी को साधने की विवशता और अर्थव्यवस्था को उबारने की मजबूरी ने कभी ड्रीम बजट पेश करने वाले चिदंबरम की इस पेशगी ने कमोबेश सभी को निराश किया है। सेंसेक्स में गिरावट इसका ताजा प्रमाण है।

बदहाली हममें से 40 फीसद लोग अति गरीब हैं। उनकी बदहाली की दास्तां किसी से छिपी नहीं है। दिन भर कमाते हैं तो रात को भोजन का इंतजाम होता हैं। अन्यथा भूखे पेट सोने को विवश होना पड़ता है। 'दिहाड़ी बजट' वाले इन लोगों की बस इतनी हसरत है कि उनका और उनके परिवार के जीवन स्तर में सुधार आए।

खुशहाली इस बजट में वित्तमंत्री ने कई अच्छी और सकारात्मक घोषणाएं की हैं। कई ऐसी भी हैं जिनमें दी गई राहत दिखती है लेकिन पीठ पीछे लगने वाली अप्रत्यक्ष चपत का अभी आभास नहीं है। लगने पर ही वह समझ में आएगी। महज 42,800 अमीरों पर टैक्स बोझ बढ़ाने से गरीबों का कितना भला होगा! उनका भला तब होगा जब भूख लगने पर पोषक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। रहने के लिए एक छोटा ही सही लेकिन स्वच्छ आवास मुहैया हो। ऐसे में बजट के माध्यम से गरीबों का अधिकाधिक कल्याण किया जाना हम सभी के लिए बड़ा मुद्दा है।

बजट का असर

प्रतिष्ठित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर ने बजटीय प्रस्तावों का अध्ययन कर क्षेत्रवार इसके असर का आकलन किया है :

उपभोक्ता वस्तुएं

दो हजार रुपये से अधिक महंगे मोबाइल फोन पर एक्साइज ड्यूटी एक प्रतिशत से बढ़ाकर छह प्रतिशत की गई। इससे मोबाइल चार-पांच प्रतिशत अधिक महंगे हो जाएंगे। नतीजतन मोबाइल फोन की मांग पर बुरा असर पड़ेगा और कालाबाजारी को प्रोत्साहन मिलेगा।

निर्माण उद्योग

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी अन्य स्कीमों में आवंटन राशि बढ़ाने से इस क्षेत्र को लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार लगातार सस्ते आवास मुहैया कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। इससे आधारभूत ढांचे के लिए दीर्घकालिक वित्त भी उपलब्ध होगा।

एफएमसीजी

सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी 18 प्रतिशत बढ़ाई गई है इससे इसके दाम बढ़ेंगे। इस क्षेत्र में कोई अन्य प्रस्ताव नहीं होने के कारण कुल मिलाकर इस उद्योग पर खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ऑटोमोबाइल

10 हजार नई बसें खरीदी जाएंगी। इससे कमर्शियल वाहन उद्योग को मुनाफा मिलने की उम्मीद है। कृषि ऋण 5,75,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,00,000 करोड़ दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी बढ़ेगी। नतीजतन ट्रैक्टरों और दोपहिया गाड़ियों की मांग बढ़ेगी।

सीमेंट

यद्यपि रेल माल भाड़े में बढ़ोतरी के कारण प्रति बैग भाड़े की कीमतों में दो-चार रुपये की बढ़ोतरी होगी जिसका सीमेंट उद्योग पर बुरा असर पड़ेगा।

थोड़ा है ज्यादा की जरूरत

सामाजिक क्षेत्र

-सुब्रत दास
(एजीक्यूटिव डायरेक्टर, सेंटर फॉर बजट एंड गवर्नेंस एकाउंटबिलिटी)

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि 'भारत एक बहुल और विविधता वाला देश है और यदि हमने सदियों से वंचित, उपेक्षित और गरीब तबके पर विशेष ध्यान नहीं दिया तो समाज के कई वर्ग पीछे छूट जाएंगे।' लेकिन इस उपेक्षित तबके की तरफ जो बजटीय आवंटन के माध्यम से ध्यान दिया गया है, वह वर्तमान जरूरतों के लिहाज से नाकाफी है।

सामाजिक सेवाओं मसलन शिक्षा, युवा कल्याण, खेल, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और सफाई इत्यादि पर पिछले साल की तुलना में खर्च में मामूली बढ़ोतरी की गई है। यदि इसको जीडीपी के लिहाज से देखा जाये तो इसमें 2012-13 (संशोधित अनुमान) के 1.7 प्रतिशत की तुलना में 2013-2014 में महज 1.9 (बजटीय अनुमान) प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। 2013-14 में इन क्षेत्रों में कुल बजटीय खर्च जीडीपी के सात प्रतिशत के आस-पास है। सामाजिक क्षेत्र में यह खर्च विकसित और कई विकासशील देशों के औसत स्तर की तुलना में काफी कम है। उल्लेखनीय है कि ओईसीडी देशों में यह औसत जीडीपी का 14 प्रतिशत है।

सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के लिहाज से केवल राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरबीएसवाई) के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसका दायरा बढ़ाते हुए कुछ अन्य श्रेणियों को इसमें शामिल किया गया है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम (एनएसएपी) के लिए बजटीय आवंटन पिछले साल के 8,382 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 9,541 करोड़ रुपये किया गया है। लेकिन इस मामूली बढ़ोतरी से लाभार्थियों का दायरा बढ़ने की गुंजाइश नहीं दिखती।

शिक्षा

इस क्षेत्र में कुल सार्वजनिक खर्च जीडीपी का 3.31 प्रतिशत है। जबकि कोठारी कमीशन ने जीडीपी का छह प्रतिशत खर्च किए जाने की अनुशंसा की है। इस बजट में शिक्षा पर कुल बजटीय आवंटन जीडीपी का 0.69 प्रतिशत किया गया है जो 2012-13 के संशोधित अनुमान (आरई) जीडीपी के 0.66 प्रतिशत की तुलना में मामूली रूप से बेहतर है। शिक्षा के अधिकार (आरटीई) एक्ट के क्रियान्वयन का जिम्मा सरकार के सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) पर है लेकिन इसके लिए बजटीय आवंटन पिछली बार की तुलना में महज 3,613 करोड़ रुपये बढ़ाया गया है। इसमें 2012-13 के 23,645 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन (आरई) की तुलना में 2013-14 में धनराशि को बढ़ाकर 27,258 करोड़ रुपये किया गया है। निर्धारित अवधि के भीतर आरटीई लक्ष्यों की प्राप्ति के लिहाज से यह नाकाफी है। स्पष्ट है कि इस तरह के अपर्याप्त बजटीय प्रावधानों से सभी बच्चों की पढ़ाई का सपना दूर की कौड़ी ही साबित होगा। नई राष्ट्रीय उच्च शिक्षा स्कीम लांच की गई है लेकिन उसके लिए भी महज 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। हालांकि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए बजटीय प्रावधान पिछले साल के 2,423 करोड़ रुपये की तुलना में इस बार बढ़ाकर 3,124 करोड़ किया गया है लेकिन यह भी 12वीं पंचवर्षीय योजना में की गई सिफारिशों की तुलना में कम है।

चुनिंदा सूचकांक

	1950-51	2010-11
आबादी *(मिलियन में)*	361	1210
प्रति व्यक्ति एक हजार पर		
जन्म दर	39.9	21.8
मृत्यु दर	27.4	7.1
जीवन प्रत्याशा *(वर्षों में)*	32.1	66.1
साक्षरता *(प्रतिशत में)*	18.3	74.04
आरएमपी *(हजारों में)*	61.8	922.2
आरएमपी *(दस हजार पर)*	1.7	7.6
बेड *(दस हजार पर)*	3.2	-

स्वास्थ्य

2012-13 में इस क्षेत्र में सार्वजनिक खर्च जीडीपी का महज एक प्रतिशत था। वैश्विक दृष्टि से इस मामले में हम निचले पायदान पर खड़े हैं। केवल स्वास्थ्य मदों में भारी खर्चे के कारण हर साल लाखों लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने को विवश होते हैं। लिहाजा स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा सुधारना सरकार के समक्ष बड़ी नीतिगत चुनौती है। बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के लिए 21,239 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यद्यपि इस मिशन का दायरा बढ़ाने की रणनीतियों के लिहाज से उम्मीद थी कि इस बार कुल स्वास्थ्य बजट में एनएचएम के हिस्से के आवंटन में बढ़ोतरी होगी लेकिन उसके बजाय इसमें गिरावट दर्ज की गई। हालांकि महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य इंश्योरेंस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरबीएसवाई) शुरू की गई है। इसमें रिक्शा-चालकों, ऑटो और टैक्सी ड्राइवर समेत गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे (बीपीएल) श्रेणी के 3.4 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है।

पेयजल और स्वच्छता

शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना तक 1,45,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। हालांकि 2011 की जनगणना के मुताबिक 43.5 प्रतिशत लोगों के पास वाटर सप्लाई की सुविधा है। 11 प्रतिशत लोग कुएं से जल प्राप्त करते हैं।

42 प्रतिशत लोग हैंडपंप/ट्यूबवेल और 3.5 प्रतिशत लोग अन्य स्रोतों से जल प्राप्त करते हैं। दूसरी तरफ स्वच्छता के मामले में तस्वीर निराशाजनक है। 51.1 घरों में अभी भी शौच की सुविधाएं नहीं हैं। समाज के पिछले वर्गों की हालत तो इस मामले में और भी दयनीय है। इसके बावजूद इस बार ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता के मामले में बजटीय आवंटन जीडीपी का महज 0.13 प्रतिशत किया गया है जो पिछले साल 0.14 प्रतिशत था।

कुल मिलाकर मानव विकास के इन बुनियादी पहलुओं पर सरकार ने अपेक्षित आवंटन नहीं किया है।

जनमत

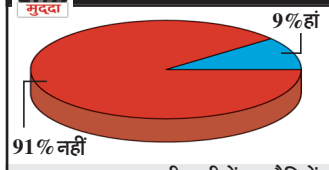

क्या आम बजट आपकी उम्मीदों-कसौटियों पर खरा उतरा?

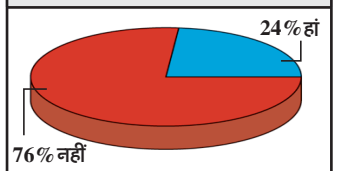

क्या आम बजट में मौजूदा आर्थिक चुनौतियों से जूझने का जज्बा दिख रहा है?

आपकी आवाज

इस बार का आम बजट न तो सरकार के आर्थिक फायदे वाला दिख रहा है और न ही आम जनता के हित में।
-राजू 09023693142@जीमेल.कॉम

बजट में आम आदमी को रिझाने से ज्यादा देश के आर्थिक सुधार की कोशिश की गई है। लेकिन, बढ़ती महंगाई और मौद्रिक असंतुलन के बीच वित्त मंत्री असहाय दिखते हैं। इस बजट से न तो देश को न ही जनता को लाभ मिलेगा।
-शुभ जीपीटी 100@जीमेल.कॉम

सरकार के पास किसी भी समस्या से निपटने के लिए राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही शक्तियां होती हैं। परंतु अफसोस कि इन दोनों ही शक्तियों का दुरुपयोग होने के कारण बजट कैसा भी पेश किया जाये, हम हमेशा फिसड्डी ही साबित होते हैं।
-वंदना एलकेओवेस्ट@जीमेल.कॉम

उद्योगों पर पड़ेगा मिला-जुला असर

-विनय खट्टर
(हेड रिसर्च (इंडीविजुअल क्लाइंट्स), एडिलवीज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड)

व्यापार संतुलन

	1949-50	2012-13
निर्यात	485	11,66,439
आयात	617	19,67,522
ट्रेड बैलेंस	-132	-8,01,083

(करोड़ में)

वित्त मंत्री के बजट से उद्योग जगत को साफ संदेश गया है कि यह उनके लिए ड्रीम बजट नहीं है। लेकिन, इसमें विनिर्माण उद्योग के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि एक अरब रुपये से अधिक प्लांट या मशीनरी स्थापित करने पर 15 प्रतिशत का निवेश अलाउंस दिया जाएगा। निराशा के इस माहौल में यह एक बड़ा कदम है।

यदि क्षेत्रवार बजट का विश्लेषण किया जाए तो तेल कंपनियों को मसलन इंडियन ऑयल कारपोरेशन और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लाभ मिलेगा क्योंकि वित्त मंत्री ने कच्चे तेल और ऑयल उत्पादों पर आयात ड्यूटी नहीं लगाई है। इसी तरह गैस क्षेत्र में नई नीति लाने और कीमत निर्धारण नीति में अनिश्चितता के बादल छांटने से केवल प्राकृतिक गैस उत्पादकों को ही लाभ नहीं मिलेगा बल्कि ऊर्जा और फर्टिलाइजर क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा।

पहला घर खरीदने पर 25 लाख तक के होम लोन पर एक लाख की अतिरिक्त ब्याज बचत से एलआइसी हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनियों को लाभ मिलेगा। इससे रियल एस्टेट सेक्टर में भी उछाल आने की उम्मीद है।

बजट में निवेश का माहौल बनाने का प्रयास किया गया है इससे कुछ सेक्टरों को अन्यों की तुलना में विशेष लाभ होगा।

एसयूवी गाड़ियों और सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से निर्माता कंपनियों पर आंशिक असर पड़ेगा। कमर्शियल गाड़ियों की चेसिस पर एक्साइज ड्यूटी 14 प्रतिशत से घटाकर 13 प्रतिशत करने पर टाटा मोटर्स और अशोक लीलैंड जैसी कंपनियों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा जवाहर लाल शहरी नवीकरण योजना के अंतर्गत 10 हजार नई गाड़ियों को खरीदने की योजना से भी इस क्षेत्र की कंपनियों को फायदा पहुंचेगा।

डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (डीडीटी) के प्रतिकूल प्रभावों को हटाने से आइटी कंपनियों पर थोड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। टीवी के सेट-टॉप बॉक्स पर कस्टम ड्यूटी पांच से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने से डीटीएच ऑपरेटरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऊर्जा उत्पादकों के लिए इस साल भी कर रियायतें बढ़ाई गई हैं।

ब्रांडेड कपड़ों पर एक्साइज ड्यूटी की दर यथावत रखने से टेक्सटाइल सेक्टर के भी फलने-फूलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर सरकार के वित्तीय सुधार के एजेंडे से उद्योग जगत को दीर्घकालिक लाभ मिलने की उम्मीद है।

निवेश का बनेगा माहौल

-दीपक मित्तल
(सीईओ, एडिलवीज टोकियो लाइफ इंश्योरेंस)

यदि देश की बचत दर को देखा जाए तो वित्त मंत्री के अनुसार यह 36 प्रतिशत से घटकर 30 प्रतिशत हो गई है। इसके बावजूद हमारी कुल सालाना बचत 500 अरब डॉलर के आस-पास बैठती है। दुर्भाग्य से इतनी बड़ी राशि के बावजूद महज सात-आठ प्रतिशत ही निवेश में तब्दील हो पाती है। संभवतया इसी कारण हमारा स्टॉक बाजार विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा संचालित होता है। इसीलिए बजट में निवेशकों को बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें सबसे पहली घोषणा इंफ्लेशन डंडेक्स बांड की हुई है। ये बांड ऐसे निवेशकों के लिए आदर्श हैं जो यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनकी बचत मुद्रास्फीति की वजह से प्रभावित नहीं हो। कर मुक्त बांड की सीमा 50 हजार करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई है। इससे टैक्स में बचत होगी।

राजीव गांधी इक्विटी स्कीम की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी गई है। इससे इक्विटी बाजार में प्रत्यक्ष या म्युचुअल फंड के जरिये पहली बार निवेश करने वाले लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा।

लंबी अवधि की बचत के लिए इंश्योरेंस बढ़िया तरीका माना जाता है। इस क्षेत्र में भी निवेश के बढ़िया अवसर प्रदान करने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर का दायरा बढ़ाने की कोशिश की गई है। अब थ्री-टायर शहरों में भी इंश्योरेंस कंपनियां दफ्तर आसानी से खोल सकेंगी।

कुछ खट्टा कुछ मीठा

कृषि

● प्रो रमेश चंद

यदि बजट में कृषि के लिए प्रस्ताव को देखें तो उसमें कई सराहनीय बातें हैं। बजट में उत्तरी क्षेत्र की संभावनाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा विकसित क्षेत्र के टिकाऊपन को सहयोग प्रदान करते हुए फसलों के विविधीकरण के लिए साधन जुटाने का प्रयास किया गया है।

हमारे 80 प्रतिशत से ज्यादा किसान लघु और सीमांत है, उन्हें बाजार में बहुत मुश्किलें आती हैं। इस संदर्भ में कृषि उत्पादन संगठनों को सहायता प्रदान करना काफी महत्वपूर्ण है। परन्तु इसके लिए काफी कम संसाधन जुटाए गए हैं। पशुधन में उत्पादन चार प्रतिशत से ज्यादा दर से बढ़ रही है। परन्तु इस दिशा में विशेष प्रयास नहीं किए गए हैं। कृषि वाणिज्यिक होती जा रही है और खर्च बढ़ रहे हैं। ऐसे में किसानों को निजी स्रोतों से लोन लेने से बचाने के लिए संस्थागत ऋण को बढ़ाना अनिवार्य है। इससे निजी निवेश को भी बढावा मिलेगा। इन सबके बावजूद बजट में ऐसी कई प्रमुख खामियां हैं, जिन पर गौर न करने से कृषि क्षेत्र पर तात्कालिक और दूरगामी दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं। इसमें मुख्य है कृषि अनुसंधान को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध न कराना। वित्त मंत्री को इस पर विचार करना चाहिए और शोध कार्यों के लिए आवंटन बढ़ाना चाहिए। कृषि भंडारण, खाद्य-प्रसंस्करण, कृषि विपणन को भी बजट में नजरअंदाज किया गया है। इस दिशा में भी तत्काल ध्यान दिए जाने की जरूरत है।

डायरेक्टर, नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च (एनसीएपी)

प्रमुख फसलों का उत्पादन

	1970-71	2011-12
खाद्यान्न	108.4	257.4
अनाज	96.6	240.2
दाल	11.8	17.2
चावल	42.2	104.3
गेंहू	23.8	93.9
ज्वार	8.1	6.0
तिलहन	9.6	30.0
गन्ना	126.4	357.7

(मिलियन टन में)

महंगाई को बढ़ाएगा बजट

● जयप्रकाश रंजन

वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बजट 2013-14 पेश करते हुए उम्मीद जताई है कि इससे महंगाई दर को थामने में सहूलियत होगी। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने जो प्रावधान किए हैं उससे आम आदमी पर महंगाई का बोझ पड़ना तय है। पेट्रोलियम और उर्वरक की कीमतों को बढ़ाने का रोडमैप पहले ही लागू किया जा चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि खाद्य उत्पादों की कीमतों में तेजी को रोकने के लिए आपूर्ति पक्ष को बेहतर बनाने के लिए वित्त मंत्री ने कोई ठोस कदम नहीं उठाये हैं। ऐसे में सभी की उम्मीदें राजकोषीय घाटे के नियंत्रण पर टिकी हुई हैं। अगर वित्त मंत्री इसे अगले वित्त वर्ष के दौरान 4.8 फीसद पर सीमित करने में सफल रहते हैं तो महंगाई की दर भी अगले वित्त वर्ष के अंत तक कम हो सकती है।

पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का कहना है कि राजकोषीय घाटे को जिस तरीके से आंकड़ों में फेर बदल कर 5.2 फीसद रहने का दावा किया गया है वह अपने आप में कई सवाल उठाता है। राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक कम होता है तो दूसरा भी कम होता है। वर्ष 2013-14 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे के 4.8 फीसद पर रहने का लक्ष्य रखा है इसके हिसाब से राजस्व घाटा 3.4 फीसद रहना चाहिए लेकिन उन्होंने इसके 3.9 फीसद रहने का लक्ष्य रखा है। आंकड़ों में इस बाजीगरी का असर महंगाई दर पर पड़ेगा। लिहाजा आम आदमी को महंगाई से खास राहत नहीं मिलने वाली है।

सरकार ने एक तरह से यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस पूरे वर्ष पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस महंगे होते रहेंगे। डीजल तो एक वर्ष में छह रुपये प्रति लीटर तक महंगा होगा क्योंकि तेल कंपनियों को इसकी इजाजत मिली है। गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत भी हर महीने बढ़ेगी। इसी तरह से वित्त मंत्री ने राज्यों की बिजली कंपनियों को अपना वित्तीय पुनर्गठन करने का प्रस्ताव जल्द से जल्द भेजने को कहा है। इससे आम जनता के लिए बिजली की दरें महंगी होंगी। ऐसे में वित्त मंत्री के आंकड़ों में भले ही महंगाई थमती दिखे लेकिन आम आदमी को इसका फायदा होता नहीं दिखता।

(विशेष संवाददाता, दैनिक जागरण)

खाद्य उत्पादों की कीमतों में तेजी को रोकने के लिए आपूर्ति पक्ष को बेहतर बनाने के लिए वित्त मंत्री ने कोई ठोस कदम नहीं उठाये हैं।

प्रति व्यक्ति उपलब्धता

	1960-61	2011-12
खाद्यतेल *(किग्रा में)*	3.2	13.8
वनस्पति *(किग्रा में)*	0.8	1.0
चीनी *(किग्रा में)*	4.8	18.1
कपड़ा *(मीटर में)*	15.0	40.5
चाय *(ग्राम में)*	296.0	728.0
कॉफी *(ग्राम में)*	80.0	95.0
घरेलू बिजली *(किलोवॉट में)*	3.4	130.9

बैंकों का विस्तार

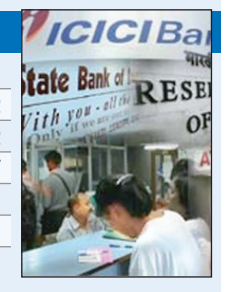

	2006	2012
एसबीआइ और उसकी सहायक शाखाएं	13,920	18,992
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	14,532	16,572
अन्य अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक	6,672	13,667
विदेशी बैंक	261	323
गैर अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक	40	55
कुल वाणिज्यिक बैंक	70,189	98,591